



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 640]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938

No. 640]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

(प्रौढ शिक्षा ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2017

का.आ. 712(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों की प्रदानगी के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग से सरकारी प्रदानगी सेवाएं सरलीकृत होती हैं, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सीधे तौर पर एक सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है; और एक व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्रौढ शिक्षा एवं कौशल विकास की केन्द्र प्रायोजित योजना, जिसे सामान्यतः **साक्षर भारत** के रूप में जाना जाता है (जिसे इसमें आगे '**योजना**' कहा गया है), को कार्यान्वित कर रही है जिसमें व्यय को आंशिक रूप से भारत की समेकित निधि और आंशिक रूप से संबंधित राज्य सरकार से वहन किया जाता है। इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और तीन हिमालयी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के अतिरिक्त सभी राज्यों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के मध्य 60:40 के अनुपात में निधियां शेयर की जाती हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए भारत सरकार और उक्त राज्यों का निधियन पैटर्न 90:10 है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा योजना को 100% वित्तपोषित किया जाता है और स्कीम को जिला और उप-जिला स्तरीय एजेंसियों और समितियों की सहायता से संबंधित राज्यों के राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

और, स्कीम 15 वर्ष व अधिक के आयु वर्ग के प्रौढ निरक्षरों को बुनियादी साक्षरता और गणना के अवसर, नव साक्षरों और स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों को कक्षा-III, V और VIII के लिए समतुल्यता कार्यक्रम के माध्यम से बुनियादी शिक्षा अवसर और सतत् शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से जीवन पर्यंत शिक्षा अवसर उपलब्ध कराती है (जिसे इसमें आगे '**व्यक्तिगत लाभार्थी**' कहा गया है);

और, स्वयंसेवी अध्यापकों द्वारा बुनियादी साक्षरता और गणना कार्यक्रम प्रदान किया जा रहा है और साक्षरता कौशल प्रदान करने के लिए साक्षरता प्रवेशिका के रूप में शिक्षण अधिगम सामग्री को संबंधित राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकारियों द्वारा विशेष रूप से विकसित और मुद्रित किया जाता है। बहुधा प्रौढ़ साक्षरता प्रवेशिका खुले बाजार में उपलब्ध नहीं होती है और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों द्वारा लाभार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। योजना में स्वयंसेवी अध्यापकों के लिए किसी मौद्रिक प्रोत्साहन का प्रावधान नहीं किया गया है;

और जबकि, स्कीम के समतुल्यता कार्यक्रम के माध्यम से बुनियादी शिक्षा के लिए शिक्षण अधिगम सामग्रियों को विशेष रूप से प्रौढ़ शिक्षुओं के लिए तैयार किया जाता है और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान या राज्य मुक्त विद्यालयों द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों द्वारा व्यक्तिगत फायदाग्राहियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। सामान्यतः ये शिक्षण अधिगम सामग्री खुले बाजार में उपलब्ध नहीं होती है। बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के लिए शिक्षण कार्यकलाप प्रदान करने में शामिल अध्यापकों या अनुदेशकों के लिए मानदेय का प्रावधान है;

और, स्कीम के अंतर्गत जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसर योजना के पात्र जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। ये केन्द्र मूलतः पुस्तकालय सेवाओं के जरिए सतत शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। इन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का प्रबंधन दो प्रेरकों (ग्राम स्तरीय समन्वयकों) द्वारा किया जाता है, जिन्हें स्कीम के मानदंडों के अनुसार मासिक मानदेय का भुगतान किया जाता है;

और, यह स्कीम राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को मानदेय आधार पर शिक्षकों या अनुदेशकों की सेवाएं और मासिक मानदेय के साथ अनुबंध आधार पर प्रेरकों तथा राज्य, जिला, ब्लॉक स्तरीय समन्वयकों की सेवाएं लेने की अनुमति प्रदान करती है (जिसे आगे 'प्राप्तकर्ता लाभार्थी' लाभ कहा गया है);

और, स्कीम के अंतर्गत मानदेय, शिक्षण एवं अधिगम सामग्रियों के रूप में उपरोक्त लाभों में भारत की समेकित निधि से आवर्ती व्यय शामिल हैं;

अतः अब आधार (वित्तीय एवं अन्य आर्थिक सहायता, लाभ एवं सेवाओं की लक्षित अदायगी) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे आगे 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) के धारा 7 के उपबंधों की अनुपालना में केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, नामतः:

1. स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तिगत फायदाग्राहियों या प्राप्तकर्ता फायदाग्राहियों के लिए अपने पास आधार नम्बर होने का साक्ष्य प्रस्तुत करना या आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया से निकलना आवश्यक होगा।
2. स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्तिगत फायदाग्राही या प्राप्तकर्ता फायदाग्राही जिसके पास आधार नम्बर नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को **31.03.2018** तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम के खण्ड 3 के उपबंधों के अनुरूप आधार नामांकन के लिए पात्र हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) में जा सकते हैं।
3. आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अनुरूप संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में योजना के कार्यान्वयन के प्रभारी संबंधित विभाग या संबंधित स्थानीय निकाय के लिए आवश्यक होगा कि वे व्यक्तिगत फायदाग्राहियों या प्राप्तकर्ता फायदाग्राहियों जिनके पास आधार नहीं है, को आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवाएं और संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र न होने के मामले में राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में योजना के कार्यान्वयन के प्रभारी संबंधित विभाग या संबंधित स्थानीय निकाय यूआईडीएआई के वर्तमान रजिस्ट्रार के समन्वयन से सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेंगे या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार के रूप में स्वयं आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेंगे;

बशर्ते जब तक वैयक्तिक फायदाग्राही या प्राप्तकर्ता फायदाग्राहियों को आधार प्राप्त नहीं हो जाता योजना के लाभ इन व्यक्तियों द्वारा निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन स्वीकृत किए जाएंगे:—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका आधार नामांकन आईडी स्लिप; या

(ii) नीचे पैरा 4 के उप-पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; तथा

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) स्थायी खाता संख्या (पीएएन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय पत्र में व्यक्ति की फोटो सहित पहचान का प्रमाणपत्र; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु यह और कि इस परियोजनार्थ राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में योजना के कार्यान्वयन के प्रभारी संबंधित विभाग या संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

4. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक तथा बाधारहित प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में योजना के कार्यान्वयन के प्रभारी संबंधित विभाग निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्था करेंगे, अर्थात्:—

(क) फायदाग्राहियों को स्कीम के अंतर्गत आधार की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाने के लिए मीडिया और राज्य शिक्षा मिशन प्राधिकरणों तथा उनकी जिला व उप-जिला स्तरीय एजेंसियों या समितियों आदि के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना द्वारा व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि वे पहले से ही नामांकित नहीं हैं तो उन्हें 31.03.2018 तक उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों में स्वयं को नामांकित करने की सलाह दी जाती है।

(ख) यदि स्कीम के उक्त फायदाग्राही अपने नजदीकी क्षेत्र जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील पर नामांकन केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन करने में समर्थ नहीं होते हैं तो स्कीम को कार्यान्वित कराने वाले संबंधित राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण और उनकी जिला तथा उप-जिला स्तरीय एजेंसी या समिति आदि के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं तैयार करने की आवश्यकता है और इस उद्देश्यार्थ प्रदत्त वेबपोर्टल के माध्यम से या संबंधित राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण और उनकी जिला तथा उप-जिला स्तरीय एजेंसियों या समितियों के साथ फायदाग्राहियों का नाम, पता, मोबाइल नम्बर और अन्य विवरण देते हुए आधार नामांकन के लिए भी अनुरोध किया जा सकता है।

5. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 8-53/2016-ई-2]

अजय तिकी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

(AE BUREAU)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2017

S.O. 712(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development in the Government of India is implementing the Centrally Sponsored Scheme of Adult Education and Skill Development commonly known as **Saakshar Bharat** (hereinafter referred to as '**the Scheme**') which involves expenditure incurred partly from the Consolidated Fund of India and partly from the fund of the concerned State Government. Presently the sharing of funds between the Government of India and the State Governments is in the ratio of 60 : 40 for all States except North-eastern Region States and three Himalayan States (Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand). The funding pattern for North-eastern Region States and Himalayan States is in the ratio of 90:10 between the Government of India and the said States. For Union Territories, the Scheme is funded hundred per cent by the Central Government and the Scheme is implemented through State Literacy Mission Authorities of the concerned States with the help of their District and Sub-district level agencies and committees;

And whereas, the Scheme provides opportunities of Basic Literacy and numeracy for adult non-literates in the age group of 15 years and above and Basic education opportunities through Equivalency Programme for class-III, V and VIII to neo-literates and school dropouts and lifelong education opportunities through Continuing Education Programme (hereinafter referred to as **‘Individual beneficiaries’**);

And whereas, the Basic literacy and numeracy programme is being imparted through Volunteer teachers and the Teaching Learning Materials in the form of Literacy Primers to be used for imparting literacy skills are specifically developed and printed by the concerned State Literacy Mission Authorities. The Adult Literacy Primers are usually not available in the open market and are provided free of cost to the beneficiaries by the State Literacy Mission Authorities. No monetary incentive is provisioned under the scheme for Voluntary teachers;

And whereas, the Teaching Learning Materials for Basic Education through Equivalency Programme of the Scheme are specifically developed for adult learners and printed by National Institute of Open Schooling or State Open Schools and are provided free of cost to the individual beneficiaries by the State literacy Mission Authorities. These Teaching Learning Materials are generally not available in the open market. There is a provision for honorarium to the teachers or instructors involved in imparting teaching activities for Basic Education Programme;

And whereas, the lifelong education opportunities under the Scheme are being provided through Adult Education Centres set up at Gram Panchayat levels in the eligible districts of the Scheme. These Centres are basically responsible for providing continuing education facilities through library services. These Adult Education Centres are being managed by two Preraks (Village Level Coordinators), who are paid monthly honorarium as per the norms of the Scheme;

And whereas, the Scheme allows State Literacy Mission Authorities to hire the services of teachers or instructors on honorarium basis and services of Preraks, and State, District, Block level Coordinators on contractual basis with monthly honorarium (hereinafter referred to as **‘Recipient beneficiaries’**);

And whereas, the aforesaid benefits in the form of honorarium, teaching and learning materials under the Scheme involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as **‘the said Act’**), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. Individual beneficiaries or Recipient beneficiaries desirous of availing the benefits under the scheme are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
2. Any Individual beneficiary or Recipient beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by **31.3.2018**, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.
3. As per Regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned local authorities or Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union Territory administration which requires an Individual beneficiary or Recipient beneficiary to furnish Aadhaar shall offer Aadhaar enrolment facilities for the Individual beneficiaries or Recipient beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the local authorities or Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union Territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the Individual beneficiaries or Recipient beneficiaries, benefits under the Scheme shall be given to such Individual beneficiaries or Recipient beneficiaries subject to the production of the following identification documents, namely:—

- (a) (i) If she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or
- (ii) A copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 5 below; and

- (b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card ; or (iii) Ration Card, or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card ; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (vii) Kisan Photo passbook; or (viii) any other documents specified by the concerned State Government or Territory Administration;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the local authorities or concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union Territory administration for that purpose.

4. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union Territory administration shall make all the required arrangements including the following, namely:—

- (a) Wide publicity through media and individual notices through the State Literacy Mission Authority and their district and sub-district level agencies or committees, etc., shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by **31.3.2018**, in case they are not already enrolled.
- (b) In case, the said beneficiaries of the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme through State Literacy Mission Authorities and their District and sub-district level agencies or committees, etc., is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may also be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other necessary details, with the concerned State Literacy Mission Authority and their district and sub-district level agencies or committees or through the web portal provided for the purpose.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette, in all States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 8-53/2016-AE-2]

AJAY TIRKEY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2017

का.आ. 713(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है; और आधार किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् **“विभाग”** के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), संस्थाओं और राज्य संसाधन केन्द्रों (जिसे इसमें इसके पश्चात् **“एसआरसी”** के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) जिसमें भारत की समेकित निधि से उपगत सौ प्रतिशत व्यय सम्मिलित है में सर्वत्र क्रियान्वयन अभिकरणों को समर्थन प्रदान करने के द्वारा प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए एनजीओ/संस्थाओं/एसआरसी के समर्थन के लिए केन्द्रीय सेक्टर स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है।

और, यह स्कीम **राज्य संसाधन केंद्रों** के माध्यम में साक्षर भारत प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए तकनीकी और शैक्षिक संसाधन सहायता के विस्तार का उपबंध करती है, और **जन शिक्षण संस्थानों** के माध्यम से प्रौढ़-निरक्षरों या नव साक्षरों और शिक्षा के प्रारंभिक स्तर प्राप्त करने वाले अन्य लक्षित फायदाग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करती है। ये राज्य संसाधन केंद्र और जन शिक्षण संस्थान रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक एजेंसियों अथवा विश्वविद्यालयों के तत्वाधान में कार्य कर रहे हैं और स्कीम के अधीन वर्ष दर वर्ष आधार पर सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं;

और, राज्य संसाधन केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए शिक्षण अधिगम तथा प्रशिक्षण सामग्री तैयार करके; कृतकारियों का साहित्य संबंधी के प्रशिक्षण; कार्य अनुसंधान, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की भविष्य की जरूरतों की पहचान हेतु नवाचारी परियोजनाओं और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से समनुदेशित किए समस्त उद्देश्यों को पूरा करने हेतु प्रासंगिक किसी अन्य कार्य के लिए नवाचारी परियोजनाओं के माध्यम से विस्तारी तकनीकी और शैक्षिक संसाधन सहायता प्रदान करते हैं;

और जबकि, राज्य संसाधन केन्द्रों में समनुदेशित की गई सेवाओं को पूरा करने के लिए मासिक परिलब्धि के आधार पर संविदात्मक कोर कर्मचारियों को लगाया गया है और बुनियादी साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों हेतु शिक्षण, अधिगम, प्रशिक्षण और अन्य सामग्री तैयार करने के लिए मानदेय आधार पर उपाय कुशल व्यक्तियों या अनुदेशकों की सेवाएं भी ली जाती हैं। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को राज्य संसाधन केन्द्र की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और राज्य संसाधन केन्द्र के कार्यक्रमों के कोई प्रत्यक्ष फायदाग्राही नहीं हैं;

और, जन शिक्षण संस्थान जिला स्तरीय संस्थाएं हैं जो निरक्षरों और नव साक्षरों के साथ-साथ स्कूल बीच में छोड़ने वालों को पहचाने गए कौशलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वे मासिक परिलब्धि के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं का प्रबंध करने के लिए मूल संविदात्मक स्टाफ की नियुक्ति करते हैं। वे अलग-अलग व्यावसायों में वास्तविक प्रशिक्षण हेतु मानदेय आधार पर अनुदेशकों और उपाय कुशल व्यक्तियों की सेवाएं भी लेते हैं। जन शिक्षण संस्थान फायदाग्राहियों के कार्य प्रदर्शन हेतु अपेक्षित अवसंरचना और कम-से-कम प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था कर रहे हैं;

और, यह स्कीम शिक्षण अधिगम सामग्री, प्रदर्शनी और प्रशिक्षण सुविधाओं (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'व्यक्ति फायदाग्राही' कहा गया है) के रूप में निरक्षरों, नव-साक्षरों और स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तारी प्रसुविधा हेतु अवसर प्रदान करती है;

और, यह योजना राज्य संसाधन केन्द्रों तथा जन शिक्षण संस्थानों को नियत सेवाओं के लिए मासिक परिलब्धियों के आधार पर तथा जब कभी आवश्यक हो शिक्षकों या अनुदेशकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'प्राप्तकर्ता फायदाग्राही' कहा गया है) की सेवाएं मानदेय के आधार अनुबंध आधार पर लेने की अनुमति प्रदान करती है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:

(1) प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक व्यक्तिगत फायदाग्राहियों या प्राप्तकर्ता फायदाग्राहियों को उनके पास आधार संख्यांक होने का सबूत पेश करना या आधार अभिप्रमाण प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक किसी ऐसे फायदाग्राही या प्राप्तकर्ता फायदाग्राही को जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31.03.2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार नामांकन के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार संबंध विभाग से अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांक सुविधाओं की प्रस्थापित करने की अपेक्षा होगी यदि उनके और संबंध ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र न होने के मामले में संबंध नहीं है तो विभाग से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर स्वयं आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी।

परंतु व्यक्ति फायदाग्राहियों या प्राप्तकर्ता फायदाग्राहियों का आधार नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्ति फायदाग्राहियों या प्राप्तकर्ता निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) नीचे पैरा 4 के उप पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट उसके द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान कार्ड; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) स्थायी खाता संख्यांक (पीएएन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय पत्र पर व्यक्ति की फोटो सहित पहचान का प्रमाणपत्र; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) संबंधित राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों और उनके अभिकरणों या समितियों द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परंतु यह और कि विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

4. योजना के अधीन व्यक्ति फायदाग्राहियों या प्राप्तकर्ता फायदाग्राहियों को सुविधाजनक तथा बाधरहित प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:—

(क) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति व्यक्ति फायदाग्राहियों या प्राप्तकर्ता फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम के अधीन मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत सूचना देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं तो उन्हें 31.03.2017 तक उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्र में स्वयं को नामांकित कराने की सलाह दी जा सकेगी।

(ख) यदि स्कीम के उक्त फायदाग्राही अपने नजदीकी क्षेत्र जैसे ब्लॉक या तहसील या तालुका जैसे निकटतम क्षेत्र में नामांकन केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण स्कीम को उक्त फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन नहीं करवा पाता है तो संबंधित विभाग से अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम के अधीन व्यक्ति फायदाग्राहियों या प्राप्तकर्ता फायदाग्राहियों से उनके संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण के पास या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेबपोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर और अन्य आवश्यक व्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर कराने का अनुरोध भी किया जा सकेगा।

5. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होगी।

[फा. सं. 8-53/2016-एई-2]

अजय तिकी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2017

S.O. 713(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development in the Government of India (hereinafter referred to as 'the Department') is implementing the Central Sector Scheme of **Support to NGOs/Institutions/SRCs for Adult Education and Skill Development** (hereinafter referred to as '**the Scheme**') by providing support to implementation agencies across Non-Government Organisations (NGOs), Institutions and State Resource Centres (hereinafter referred to as 'SRCs') which involves hundred per cent expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas, the Scheme provides extension of technical and academic resource support to Saakshar Bharat and Adult Education programme through **State Resource Centres** and also provides skill training opportunities to adult non-literates or neo-literates and other targeted beneficiaries having rudimentary level of education through **Jan Shikshan Sansthan**s. These State Resource Centres and Jan Shikshan Sansthan are

functioning under the aegis of Registered Voluntary Agencies or Universities and are getting grants-in-aid under the Scheme on year to year basis;

And whereas, the State Resource Centres extend technical and academic resource support through preparation of teaching learning and training materials for the Adult Education programme; training of literacy functionaries; action research; innovative projects to identify future needs of the Adult Education programme and any other function incidental to accomplishment of the overall objectives of the National Literacy Mission Authority or specifically assigned by the Ministry of Human Resource Development, Government of India;

And whereas, the State Resource Centres engage the services of core contractual staff for undertaking the assigned services on monthly emolument basis and also hire the services of Resource Persons or Instructors on honorarium basis for development of Teaching, Learning, Training and other materials for Basic Literacy and Adult Education programmes. The services of State Resource Centres are provided to the Adult Education programme and there are no direct beneficiaries of State Resource Centres' interventions;

And whereas, the Jan Shikshan Sansthan are district level institutions providing vocational training to non-literates and neo-literates as well as school dropouts in identified skills and they engage the services of core contractual staff for managing the vocational training services on monthly emolument basis. They also hire the services of Instructors or Resource Persons on honorarium basis for actual training in different vocations and the Jan Shikshan Sansthan are also arranging to provide requisite infrastructure and minimum training material for demonstration to the beneficiaries;

And whereas, the Scheme provides opportunities for extending benefits of Vocational Training programmes to non-literates, neo-literates and school dropouts in the form of teaching, learning materials, demonstration and training facilities (herein after referred to as '**Individual beneficiaries**');;

And whereas, the Scheme allows State Resource Centres and Jan Shikshan Sansthan to hire services of contractual staff for undertaking the assigned services on monthly emolument basis and services of teachers or instructors on honorarium basis as and when required (hereinafter referred to as '**Recipient beneficiaries**');;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as '**the Act**'), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

- (1) Individual beneficiaries or Recipient beneficiaries desirous of availing the benefits under the Scheme for Adult Education and Skill Development are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any Individual beneficiary or Recipient beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme for Adult Education and Skill Development, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to make application for Aadhaar enrolment by **31.3.2017** provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of Section 3 of the Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) to get enrolment for Aadhaar.
- (3) As per Regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department through its implementation agencies which requires an Individual beneficiary or Recipient beneficiary to furnish Aadhaar, is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department through its implementation agencies is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Department itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the Individual beneficiaries or Recipient beneficiaries, benefits under the said Scheme shall be given to such Individual beneficiaries or Recipient beneficiaries subject to the production of the following identification documents, namely:-

- (a) (i) If she or he has enrolled, her/his Aadhaar Enrolment ID slip; or
- (ii) A copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 4 below; and

- (b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (vii) Kisan Photo passbook; or (viii) any other documents specified by the concerned State Literacy Mission Authorities and their agencies or committees;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department for that purpose.

- (4) In order to provide convenient and hassle free benefits to the Individual beneficiaries or Recipient beneficiaries, the Department through its implementation agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:-

- (a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to Individuals beneficiaries or Recipient beneficiaries under the Scheme for Adult Education and Skill Development to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centre available in their areas by **31.3.2017** in case they are not already enrolled.
- (b) In case, the said beneficiaries of the Scheme are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Tehsil or Taluka, the concerned Department through its implementation agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the Individual beneficiaries or Recipient beneficiaries under the Scheme for Adult Education and Skill Development may also be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other necessary details with their concerned implementation agency or through the web portal provided for the purpose.

- (5) This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 8-53/2016-AE-2]

AJAY TIRKEY, Jt. Secy.